will be taken up after the work on parallel Broad Gauge line between Dindigul and Madurai, at present in progress, is completed.

घाटे में चल रहे रेल मार्ग

552. **श्री राम नरेश यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कई रेल मार्ग हैं, जिन पर रेलवे को आर्थिक हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेल मार्गों की कुल संख्या कितनी है और क्या सरकार ने इन रेल मार्गों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और ये प्रयास कब और किन मार्गों के लिए किए गए थे?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) से (ग) रेल मार्गों के वित्तीय परिणामों का ऐसा कोई आकलन नहीं किया जाता है। तथापि, शाखा लाइनों के वित्तीय संचालन का अध्ययन हर वर्ष किया जाता है। 1987-88 के लिए किये गये इस प्रकार के अध्ययन के परिणामों के आधार पर 145 शाखा लाइनें अलाभप्रद पायी गयी थीं।

अलाभप्रद शाखा लाइनों की आमदनी बढ़ाने और संचालन व्यय को यथा संभव कम करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

1. ऐसी गाड़ियों को रद्द करना जिनमें बहुत कम संख्या में यात्री यात्रा करते हैं।

2. अलाभप्रद स्टेशनों/हाल्टों को बन्द करना अथवा उन्हें ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्ट में बदलना।

3. यात्री और माल गाड़ियों के स्थान पर मिश्रित गाड़ियां चलाना।

4. "केवल एक इंजन" प्रणाली लागू करना।

5. कर्मचारियों की संख्या में कटौती।

6. खंड पर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम।

"रेनफेड एग्रीकल्चर प्लान : स्टेट्स टोल्ड टू स्पीड अप प्रोपोजल्स" शीर्षक से समाचार

553. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1989 के "दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "रेनफेड एग्रीकल्चर प्लान: स्टेट्स टोल्ड टू स्पीड अप प्रोपोजल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार को अब तक ऐसे किन-किन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं जिनसे इस योजना के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): (क) और (ख) जी, हां। सभी 16 राज्यों ने 1989-90 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और वर्षा सिंचित खेती के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना कार्यान्वयन करने हेतु केन्द्रीय भागीदारी भी निर्मुक्त की गई है।

झुग्गी-झोपड़ी-निवासियों की सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

554. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निवर्तमान उपराज्यपाल ने माह जुलाई, 1989 में जीवन-यापन की बेहतर स्थिति के लिए दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों से सामूहिक आवास समितियां बनाने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण वर्ष 1983 में गठित की गई सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन नहीं कर पाया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों की सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटन करने के लिए कोई योजनाएं बनाई है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों के विकासार्थ धनराशि का कम उपयोग

555. **श्री राम जेठमलानी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गन्दी-बस्तियों के विकासार्थ धनराशि के कम उपयोग के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्लम फन्डस वेयर नोट यूज्ड फुल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रशासन दिल्ली की गन्दी